MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Commentary

कुर्रम में जारी साम्प्रदायिक संघर्ष: दावे और हकीक़त

आशीष शुक्ल

दिसंबर 04, 2024

सारांश

पाकिस्तान में सरकार और संस्थाएं कुर्रम में जारी हिंसा के मूल कारणों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए जरुरी प्रयास करने में पूरी तरह विफल रहे हैं|

वर्तमान समय में पाकिस्तानी समाज आतंरिक रूप से अत्यधिक ध्रुवीकृत और विभाजित प्रतीत होता है| पाकिस्तान के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयास करने वाले महत्वपूर्ण लोगों, जिसमें मुहम्मद अली जिन्ना भी शामिल हैं, ने इसकी कल्पना भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के लिए एक ऐसे वतन के रूप में की थी जहाँ वह (मुसलमान) किसी अन्य समुदाय के प्रभुत्व से बाहर रहते हुए, निर्भीक रूप से अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रख सके| हालाँकि वहाँ के पढ़े-लिखे जागरुक समाज के एक छोटे से तबके, जिसका वहाँ की राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था में कोई खास प्रभाव नहीं हैं, को जल्द ही इस बात का आभास हो गया था कि इस्लाम के भीतर मौजूद विभिन्न सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय एक-दूसरे से दुश्मनी करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे|

एक राष्ट्र के रूप में पिछले कई दशकों के दौरान वहाँ के राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व द्वारा बनायी और लागू की गयी नीतियों के कारण पाकिस्तानी समाज ने कुछ हद तक सांप्रदायिक हिंसा को अपने भीतर आत्मसात कर लिया| इस बात को दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा का एक तरह से सामान्यीकरण हो गया है| बड़े पैमाने पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा और उसके फलस्वरूप होने वाले जान-माल के नुकसान ने अब केंद्र और प्रान्तों में सत्ताधीन राजनीतिक नेताओं की अंतरात्मा को झंझोड़ना बंद कर दिया है| सत्ता के इन गलियारों से अब निंदनीय वक्तव्यों को जारी करने, हिंसा में लिप्त समुदायों से शांति के लिए अपील करने, समितियां गठित करने और कबीलाई जिरगा के

माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने जैसे आधे-अधूरे कदम उठाए जाने के अतिरिक्त कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है| वर्तमान समय में खैबर पख्तुन्ख्वा प्रान्त के कुर्रम जिले में जारी सांप्रदायिक हिंसा पर भी उसी पुराने घिसे-पिटे तौर-तरीकों के माध्यम से प्रतिक्रियाएँ दी जा रही है|

हिंसा का वर्तमान चरण

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी सांप्रदायिक संघर्ष में अब तक 130 से अधिक जानें जा चुकी हैं जबकि 186 लोग घायल हुए हैं|[1] वैसे तो कुर्रम में जारी सम्प्रदायिक हिंसा का एक लम्बा इतिहास रहा है| हालाँकि वर्तमान समय में हो रही इस हिंसा का प्रारंभ सितम्बर 2024 में होता है जब सुन्नी इस्लाम को मानने वाले कबीलाइयों ने पाराचिनार, जो कुर्रम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, में शिया इस्लाम के अनुयायियों पर हमला बोल दिया| इस हमले में कुल 46 लोगों की मौत हुई जिसमें 41 शिया इस्लाम को मानने वाले थे|[2] इसके अतिरिक्त दर्जनों अन्य घायल भी हुए| इस हमले के बाद जिला प्रशासन ने एक स्थानीय जिरगा से दोनों पक्षों के बीच बात-चीत के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए गुजारिश की|

[1] "Ceasefire Reached in Pakistan's Kurram after days of clashes", *The Indian Express*, 2 December 2024.

[2] Arun Anand, "Kurram Violence: Sunni Establishment's War Against Shias in Pakistan", *News18,* 26 November 2024.

स्थानीय जिरगा बात-चीत के माध्यम से मामले का हल खोज ही रहा था कि 12 अक्टूबर को सवारी गाड़ियों के एक काफिले को निशाना बनाया जिसमें 15 लोगों की मौत हुई|[3] इस हमले ने स्थानीय जिरगा द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों को गंभीर चोट पहुंचाई| इसके तुरंत बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पेशावर और कुर्रम को जोड़ने वाले मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया| बढ़ती हिंसा के बीच कुर्रम जिले के आठ लाख बाशिंदे लगभग तीन महीने तक अलग-थलग हो गए तथा इस दौरान उन्हें जरुरी सामानों की भी आपूर्ति नहीं हो सकी| पेशावर-कुर्रम सड़क सहित अन्य बंद सड़कों को आवागमन के लिए खोलने को लेकर वहाँ के लोगों ने 21 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जिसके दौरान पाराचिनार में सभी विद्यालय और बाजार बंद रहे|[4] इसके बाद भी जब मुख्य सड़कों को नहीं खोला गया तो 7 नवम्बर को लोगों ने पाराचिनार से एक बड़ा जुलूस निकाला और सड़कों को खोलने की अपनी माँग को फिर से दोहराया|[5]

इस जुलूस के परिणामस्वरूप स्थानीय अधिकारियों ने हर हफ्ते तीन बार गाड़ियों के काफिले को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया लेकिन आश्वासन के फलीभूत होने के पहले ही, बीते 21 नवम्बर को 200 गाड़ियों के काफिले, जो पुलिस सुरक्षा में पाराचिनार से पेशावर जा रहे थे, को निचले कुर्रम के मंदोरी चारखेल क्षेत्र में निशाना बनाया गया जिसमें सात महिलाओं और एक छोटी लड़की समेत 41

[3] Abid Hussain, "Why Sectarian Tensions Continue to Simmer in Pakistan's Kurram District", *Al Jazeera,* 12 November 2024.

[4] "Kurram People Protest Closure of Roads", *Dawn,* 22 October 2024.

[5] "Massive Protest in Kurram Against Closure of Roads", *Dawn*, 8 November 2024.

लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि कम से कम 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए|[6] इसके तुरंत बाद 23 नवम्बर की रात को पाराचिनार के सशस्त्र समूहों ने निचले कुर्रम के बगान बाज़ार और आस-पास के गांवों पर हमला कर दिया जिसमें 21 लोगों की मौत हो गयी तथा 30 लोग घायल हुए|[7] जैसा कि पहले कहा गया है कि इस चरण की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 130 से अधिक लोगों कि जान जा चुकी है और सैकड़ों अन्य घायल अवस्था में हैं|

सरकारी दावे और जमीनी वास्तविकता

पाकिस्तान में धर्म आधारित सांप्रदायिक हिंसा कोई नई अवधारणा नहीं है| यहाँ यह कहना कत्तई अतिसंयोक्ति नहीं होगा कि पाकिस्तान और सांप्रदायिक हिंसा में एक गहरा सम्बन्ध है| कुर्रम समेत सम्पूर्ण पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा का एक लम्बा इतिहास रहा है जिसे समझने के उसकी तह में जाना अनिवार्य है| इस्लामाबाद, पेशावर और रावलपिंडी में बैठे राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व द्वारा इस हिंसा को रोकने के लिए किए गए प्रयास नाकाफी और अप्रभावी साबित हो रहे हैं| आधिकारिक वक्तव्यों के माध्यम से यह कहीं न कहीं यह संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है कुर्रम जिले में लगातार हो रही हिंसा के पीछे विभिन्न

[6] Flora Drury, "More than 40 Dead After Gunmen Attack Passenger Vehicles in Pakistan", *BBC*, 22 November 2024.

[7] Javed Hussain and Umer Farooq, "Rampage in Kurram Claims 21 More Lives", Dawn, 24 November 2024.

कबीलों के बीच लंबे समय विद्यमान अनसुलझे जमीनी विवाद हैं| हालाँकि वास्तविकता इससे कुछ अलग प्रतीत होती है|

अन्य पड़ोसी जिलों से हटकर, कुर्रम के लोगों का एक अलग सांप्रदायिक चरित्र है| अन्य पड़ोसी जिलों के विपरीत कुर्रम के कबीलाई समुदायों–बंगश, मंगल, मक्बल, परचाम्कानी, और तूरी–में शिया इस्लाम को मानने वालों की अधिकता है| यद्यपि पाकिस्तान में जनगणना के दौरान इस्लाम के भीतर उपस्थित विभिन्न समुदायों की अलग-अलग गिनती नहीं की जाती है, लेकिन कुछ अन्य सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से कुर्रम में 58% सुन्नी (मुख्यतः देवबंदी) और 42% शिया हैं|[8] इनमें तूरी, कुर्रम का सबसे बड़ा समूह, एक मात्र ऐसा पश्तून कबीला है जो पूरी तरह से शिया इस्लाम को मानता है, बंगश पश्तून शिया और सुन्नी दोनों के अनुयायियों में विभाजित हैं जबकि मक्बल, परचाम्कानी, मंगल और मोसाजई प्राथमिक रूप से सुन्नी इस्लाम के अनुयायी हैं|[9]

शिया इस्लाम के अनुयायियों, विशेषकर तूरी कबीलाइयों ने ऐतिहासिक रूप से अक्सर सुन्नी अतिवादियों, अफ़ग़ान तालिबान और बाहर से आने वाले अरब लड़ाकों का पुरजोर विरोध किया है| उनकी उत्पत्ति और शिया इस्लाम में विश्वास के कारण ब्रिटिश उन्हें पड़ोस के अन्य मुसलमानों से अलग मानते थे| द्वितीय अफ़ग़ान युद्ध 1877 में तूरी समुदाय ने न केवल अंग्रेज जनरल रोबर्ट्स को रास्ता दिया था बल्कि उनसे (ब्रिटिश) इस क्षेत्र के प्रशासन को चलाने का अनुरोध भी

[8] Zia Ur Rehman, **"**The Roots of Kurram's Cycles of Bloodshed**"**, *Dawn*, 1 December 2024.

[9] Ibid.

किया था|[10] तूरी समुदाय को यह डर था कि पड़ोस के सुन्नी कबीले, विशेषकर मंगल समूह उन पर आक्रमण करेंगे| इस तरह जब 1892 में कुर्रम एजेंसी की स्थापना हुई तो ब्रिटिश राज ने इस क्षेत्र को अपने प्रशासन के अंतर्गत रखा|[11]

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव

इस वृहत्तर क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक एवं भू-रणनीतिक परिस्थितयों ने भी कुर्रम को प्रभावित किया| चाहे वह 1979 में ईरान में क्रांति हो या सोवियत संघ का अफ़ग़ानिस्तान में हस्तक्षेप, दोनों ने इस क्षेत्र में कट्टरता को बढ़ावा दिया| जनरल जियाउल हक़ के शासनकाल में कुर्रम को मुजाहिदीन लड़ाकों के अफ़ग़ानिस्तान युद्ध में शरीक होने के लिए एक लांचपैड की तरह इस्तेमाल किया गया| सुन्नी देवबंदी मुजाहिदीन की इस क्षेत्र में बढ़ती संख्या तथा अफ़ग़ान युद्ध की हिंसा ने शिया अनुयायियों को जल्द ही अपनी चपेट में ले लिया| यह कोई संयोग नहीं है कि कुर्रम के शिया अनुयायियों ने 2001 में अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के दौरान तोरा-बोरा की पहाड़ियों से उतरकर भाग रहे तालिबान और अल-क़ायदा के लड़ाकों को शरण देने से मना कर दिया था| यह जनरल

[10] Mariam Abou Zahab, "'It's Just a Suni-Shi'a Thing': Sectarianism and Talibanism in FATA (Federally Administered Tribal Areas) of Pakistan", in Brigitte Marechal and Sami Zemni (eds), *The Dynamics of Sunni-Shia Relationships: Doctrine, Transnationalism, Intellectuals and the Media,* London, Hurst & Company, 2013.

[11] Ibid.

परवेज़ मुशर्रफ की "खरगोश के साथ भागने और शिकारियों के साथ शिकार करने" की नीति के विरुद्ध था|

वर्तमान समय में केंद्र और प्रान्त की सरकारें और सैन्य नेतृत्व प्रमुख रूप से कुर्रम हिंसा को कबीलाई समूहों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद से जोड़कर देखते हैं| इसमें कोई दो राय नहीं है कि विरोधी शिया और सुन्नी समूहों के बीच दशकों पुराने जमीनी विवाद हैं लेकिन इसका यह कत्तई मतलब नहीं है कि यह अनसुलझा विवाद ही वर्तमान हिंसा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं|

आधे-अधूरे आधिकारिक प्रयास

गौरतलब है कि अगस्त 2023 में खैबर पख्तुन्ख्वा की प्रांतीय सरकार ने एक बाउंड्री कमीशन गठित किया था जिसने कबीलों के वयोवृद्ध लोगों के साथ मिलकर जमीन सम्बंधित विवाद सुलझाने का प्रयास किया| हालाँकि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है लेकिन वह न तो आम लोगों के लिए उपलब्ध है और न ही उसकी सिफारिशों पर अभी तक अमल किया गया है| खैबर पख्तुन्ख्वा सरकार, कमीशन की सिफारिशों को आम लोगों को उपलब्ध न कराए जाने का कारण 'साम्प्रदायिक संवेदनशीलता' बता रही है जो निश्चित रूप से इस हिंसा के मूल कारण "शिया-सुन्नी विवाद" की ओर इशारा करता है| कुछ विश्लेषक इसे

सीधे-सीधे शिया-सुन्नी विवाद न मानकर सुन्नी-देवबंदी व शिया अनुयायियों के बीच का संघर्ष मानते हैं| हालाँकि सरकार अभी भी इस पर हीला-हवाली करती नजर आ रही है| 21 नवम्बर को हुई हिंसा के बाद जागृत हुई प्रांतीय सरकार ने कुर्रम में कानून व्यवस्था सुधारने व शांति स्थापना के लिए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें प्रान्त के कानून मंत्री आफताब आलम और मुख्य सचिव नदीम असलम चौधरी भी शामिल थे| इस प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय जिरगा के साथ मुलाकात की जिसके बाद आफताब आलम ने कहा कि सरकार ने कुर्रम में जमीनी विवादों को निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय कमीशन गठित करने का निर्णय लिया है|[12] उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले कई कमीशनों के विपरीत इस बार यह कमीशन सभी पक्षों की इच्छा के आधार पर गठित किया जाएगा और यह विवादों को सुलझाने में सफल रहेगा|

निष्कर्ष

इसमें शायद ही कोई संदेह बाकी रह गया है कि कुर्रम में जारी हिंसा के मूल में वहाँ की जनसांख्यिकी और विभिन्न कबीलाई समूहों की धार्मिक-सांप्रदायिक मान्यताओं के मध्य वैचारिक संघर्ष है जिसे वहाँ की सरकारें और संस्थाएं दोनों ही खुले रूप से स्वीकार नहीं करती हैं| यदि पाकिस्तान में मायने रखने वाली

[12] Nadir Guramani, Javid Hussain and Arif Hayat, "KP to Form High-Powered Commission to Settle Kurram Land Disputes Among Warring Tribes", *Dawn,* 23 November 2024.

संस्थाएं समस्या की वास्तविकता एवं उसके मूल में उपस्थित कारणों को अनदेखा करती रहेंगी तो उसका समाधान हमेशा उनकी पहुँच से दूर ही रहेगा| कुर्रम में आज जो कुछ भी हो रहा है यदि समय रहते उसे ठीक करने का जरुरी प्रयास न किया गया तो यह देश के अन्दर सामाजिक ताने-बाने को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और साथ ही अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में अशांति बढ़ाने का कार्य करेगा|

About the Author

Dr. Ashish Shukla is Associate Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2024

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses